

All Inclusive IAS - Prelims 2024

← English video

Economy Class-03

हिंदी वीडियो →

RBI's report on State Finances

News Indian Express, 14-Dec-2023 Report: <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/OSTATEFINANCES202324/E45F66372EEBC4743AE4E9BED92EE85FF.PDF>

Report	State Finances: A Study Of Budgets of 2023-24	राज्य वित्त: 2023-24 के बजट का अध्ययन
Theme	Revenue Dynamics and Fiscal Capacity of Indian States	भारतीय राज्यों की राजस्व गतिशीलता और राजकोषीय क्षमता
By	Released by RBI every year (latest in December 2023)	RBI द्वारा हर साल जारी (नवीनतम दिसंबर 2023 में)

Points from RBI Press release (Dec 11, 2023): https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=56910

State's Fiscal deficit in 2022-23 was 2.8% of GDP
- It improved due to reduction in revenue deficit

Estimate for 2023-24:

- Revenue deficit : near zero (improvement)
- Capital expenditure : 2.9% of GDP (improvement)
- Debt to GDP ratio : 27.6% (improvement)

States can increase non-tax revenue by:

- better management of PSUs
- increasing royalties from mining
- increasing user charges on electricity, water and other public services

$$TB = \frac{\% \text{ change in tax revenue}}{\% \text{ change in GDP}}$$

Tax buoyancy increased due to GST

2022-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा GDP का 2.8% था
- राजस्व घाटा कम होने से इसमें सुधार हुआ

2023-24 के लिए अनुमान:

- राजस्व घाटा : शून्य के करीब (सुधार)
- पूंजीगत व्यय: GDP का 2.9% (सुधार)
- ऋण-जीडीपी अनुपात: 27.6% (सुधार)

राज्य अपना गैर-कर राजस्व बढ़ा सकते हैं:

- सरकारी कॉम्पनियों का बेहतर प्रबंधन करके
- खनन से रॉयल्टी बढ़ाकर
- बिजली, पानी और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर यूजर चार्ज बढ़ाकर

GST के कारण टैक्स बोयेन्सी (कर उछाल) में वृद्धि हुई

Capital Expenditure

NEWS The Hindu Business line: 27-Dec-2023

<https://www.thehindubusinessline.com/data-stories/up-and-bihar-get-maximum-special-assistance-for-capital-expenditure-and-investment/article67679914.ece>

Special Assistance to States for "Capital Expenditure"

- This scheme was launched in 2020-21 by Finance Ministry.
- Central govt gives 50-year interest free loan to states.
- Funds can be used for ongoing and new "capital projects"
- It was launched to help states provide covid relief work? No!!!

- यह योजना वित्त मंत्रालय ने 2020-21 में शुरू की थी
- केंद्र सरकार राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण देती है
- इस पैसे का उपयोग, पहले से चल रहे, साथ ही, नई "पूंजी परियोजनाओं" के लिए किया जा सकता है
- यह राज्यों को कोविड राहत कार्य में मदद के लिए शुरू की गई थी ? नहीं!!!

Govt focuses on Capex because it has high multiplier effect.

सरकार कैपेक्स पर ध्यान इसलिए देती है क्योंकि कैपेक्स का उच्च गुणक प्रभाव होता है।

Effective Capital Expenditure

- Grants-in-aid given by centre to states, to create capital assets, is shown in Union Budget as "revenue expenditure".
- Therefore, Centre now uses the word "Effective Capital Expenditure" which includes capex by centre as well as grants to states for capex.

$$\text{Effective Capex} = \text{Capex by Centre} + \text{Grants given by Centre to States for Capex}$$

पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए सहायता अनुदान को केंद्रीय बजट में "राजस्व व्यय" के रूप में दिखाया जाता है।

इसलिए, केंद्र अब "प्रभावी पूंजीगत व्यय" शब्द का उपयोग करता है जिसमें केंद्र द्वारा पूंजीगत व्यय के साथ-साथ केंद्र द्वारा राज्यों को कैपेक्स के लिए अनुदान शामिल है।

$$\text{प्रभावी कैपेक्स} = \text{केंद्र द्वारा कैपेक्स} + \text{कैपेक्स के लिए राज्यों को केंद्र द्वारा दिया गया अनुदान}$$

Crowding-out: increase in govt spending decreases private spending

- Govt borrows more money. Less money for private companies to borrow and invest.
- Govt raises taxes. People have less money to spend.

Crowding-in: increase in govt spending increases private spending (e.g. during slowdown)

- Govt investment makes private investment more productive (infra in industrial township).
- Govt spending gives more money to people to spend.

क्राउडिंग-आउट: सरकारी खर्च में वृद्धि से निजी खर्च में कमी
➤ सरकार अधिक पैसा उधार लेती है। निजी कंपनियों के लिए उधार लेके निवेश करने के लिए कम पैसा बचता है।
➤ सरकार टैक्स बढ़ाती है। लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है।

क्राउडिंग-इन: सरकारी व्यय में वृद्धि से निजी व्यय में वृद्धि होती है (जैसे मंदी के दौरान)

- सरकारी निवेश निजी निवेश को अधिक उत्पादक बनाता है (औद्योगिक टाउनशिप में इन्फ्रा)।
- सरकारी खर्च से लोगों को खर्च करने के लिए अधिक पैसा मिलता है।

Separate explanation videos are available in English & Hindi

अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं

<p>Prelims 2013 Economic growth in country X will necessarily have to occur if</p> <p>a) there is technical progress in world economy b) there is population growth in X c) <u>there is capital formation of X</u> d) volume of trade grows in world economy</p>	<p>The diagram shows a flow starting from 'Cheap loan' (with a bank icon). This leads to two parallel paths: 'Companies invest more' (with a factory icon) and 'People spend more' (with an icon of people and a car). Both paths converge to 'Economic growth' (with a globe icon).</p>	<p>X देश में आर्थिक संवृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि</p> <p>a) विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है b) X में जनसंख्या वृद्धि होती है c) X में पूँजी निर्माण होता है d) विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है</p>	
<p>Prelims 2014</p> <p>If interest rate is decreased in an economy, it will</p> <p>a) decrease consumption expenditure in economy b) increase tax collection of Government c) <u>increase investment expenditure in economy</u> d) increase total savings in economy</p>		<p>किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है, तो वह</p> <p>a) अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा b) सरकार के कर संग्रह बढ़ाएगा c) अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा d) अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा</p>	
<p>Prelims 1995</p> <p>The main reason for low growth rate in India, inspite of high rate of savings and capital formation is:</p> <p>a) high birth rate b) low level of foreign aid c) low capital output ratio d) <u>high capital-output ratio</u></p>	<p>Prelims 2018</p> <p>Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to</p> <p>a) weak administrative machinery b) illiteracy c) high population density d) <u>high capital-output ratio</u></p>	<p>बचत और पूँजी निर्माण की उच्च दर के बावजूद भारत में कम विकास दर का मुख्य कारण है:</p> <p>a) उच्च जन्म दर b) विदेशी सहायता की कमी c) कम पूँजी-उत्पाद अनुपात d) उच्च पूँजी-उत्पाद अनुपात</p>	<p>उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूँजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है ?</p> <p>a) कमजोर प्रशासन तंत्र b) निरक्षरता c) उच्च जनसंख्या घनत्व d) उच्च पूँजी-उत्पाद अनुपात</p>

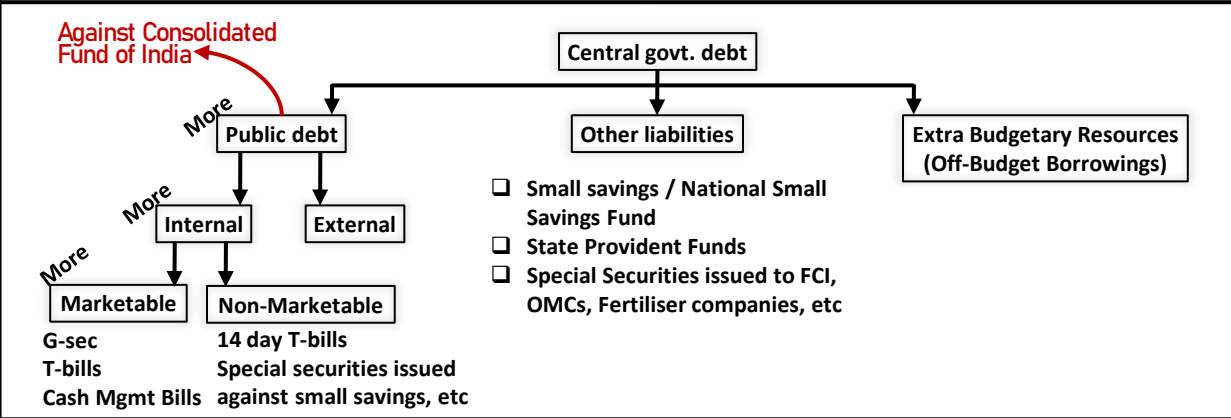
Govt Debt

Status Paper on Govt Debt <https://dea.gov.in/public-debt-management>

- Published every year by Department of Economic Affairs (Finance Ministry) since 2010
- Latest edition published in October 2023 for FY 2021-22

सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र

- 2010 से आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है
- नवीनतम संस्करण अक्टूबर 2023 में प्रकाशित हुआ (2021-22)



<https://dea.gov.in/sites/default/files/Status%20Paper%20on%20Government%20Debt%20for%202021-22.pdf>

General Government Debt is 83.3% of GDP
Central Government Debt is 59.1% of GDP

95.3% of Central govt debt is in domestic currency.
Sovereign external debt is 4.7%, implying low currency risk.

Share of marketable securities in internal debt is 76.9 %
Public debt in India is primarily contracted at fixed interest rates.

सामान्य सरकारी ऋण GDP का 83.3% है
केंद्र सरकार का ऋण GDP का 59.1% है

केंद्र सरकार के ऋण का 95.3% घरेलू मुद्रा में है।
सॉवरेन विदेशी ऋण 4.7% है, जो कम मुद्रा जोखिम को दर्शाता है।

आंतरिक ऋण में बिक्री योग्य प्रतिभूतियों का हिस्सा 76.9% है।
भारत का सार्वजनिक ऋण मुख्य रूप से निश्चित ब्याज दरों पर है।

Prelims 2013

In India, deficit financing is used for raising resources for

(a) economic development
(b) redemption of public debt
(c) adjusting the balance of payments
(d) reducing the foreign debt

भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है?

a) आर्थिक विकास के लिए
b) सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए
c) भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए
d) विदेशी ऋण कम करने के लिए

External Debt of India

\$ 625 billion

79% non-govt entities

It is 16% of India's GDP

21% Govt

It is 4% of India's GDP

55% is in \$ 30% is in ₹

80% Long term

20% Short term



International Debt Report:
Published by World Bank every year.
For 121 low & middle income countries.

India's External Debt: A Status Report
Published every year by DEA (FinMin)

Currency Risk / Forex Risk



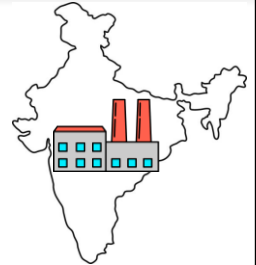
Exchange rate when taking loan: \$1 = ₹60

You take \$ 1 billion loan

You get ₹ 6,000 crore

If exchange rate remains \$1 = ₹60, you pay ₹ 6,600 crore

If exchange rate becomes \$1 = ₹70, you pay ₹ 7,700 crore

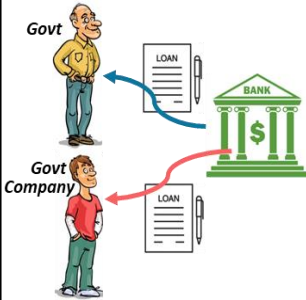


Unfavourable exchange rate movement, such as depreciation of Indian rupee, can increase burden of external debt.

विनिमय दर में प्रतिकूल परिवर्तन, जैसे भारतीय रुपये का मूल्यहास, विदेशी ऋण के बोझ को बढ़ा सकता है।

I have already taken ₹ 1 crore loan.
If I take more loan, my financial distress will be exposed.
Rather, I will ask my son to take loan in his name.

Off-Budget Borrowings बजट-बाहरी उधारियाँ



- Loan taken by public institution e.g. FCI
 - Not counted in Fiscal deficit
 - Not counted in Budget
 - Counted in Govt debt
 - Repayment is done from govt budget
- Purpose? Anything (road, subsidy, etc)

Centre uses this method to make fiscal deficit number look good.
States use this method because they don't need Centre's consent to give guarantee against a loan.

- सार्वजनिक संस्थान (जैसे FCI) द्वारा लिया गया ऋण
- राजकोषीय घाटे में नहीं गिना जाता है
- बजट में नहीं गिना जाता है
- सरकारी कर्ज में गिना जाता है
- पुनर्भुगतान सरकारी बजट से किया जाता है
- उद्देश्य ? कुछ भी (सड़क, सब्सिडी, आदि)

केंद्र इसका इस्तेमाल करता है, राजकोषीय घाटे के आंकड़े अच्छे दिखाने के लिए।
राज्य इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें ऋण की गारंटी देने के लिए केंद्र की सहमति नहीं चाहिए होती है।

Budget

Who prepares Budget?

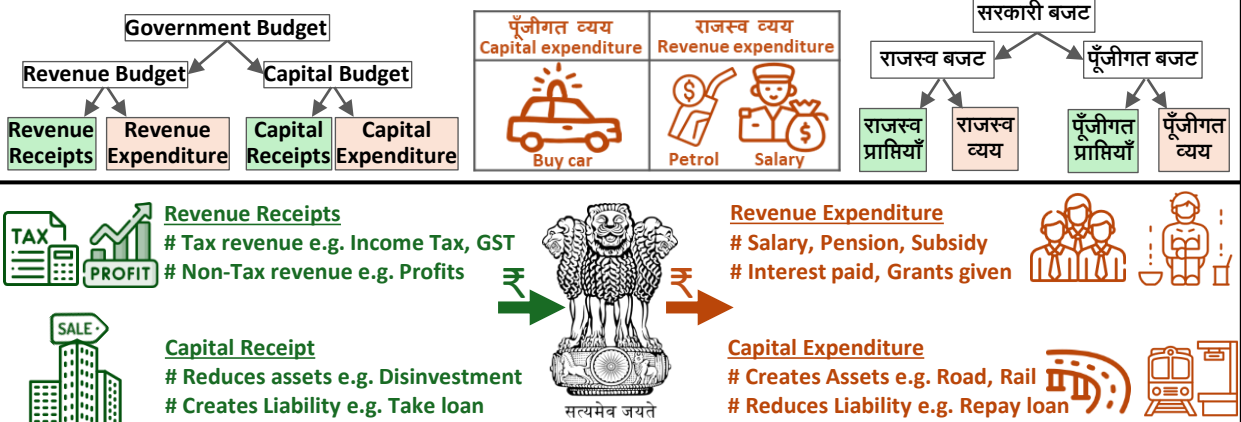
Department of Economic Affairs under Finance ministry

बजट कौन तैयार करता है?

वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग

Article 112 → Annual Financial Statement shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure

अनुच्छेद 112 → वार्षिक वित्तीय विवरण में राजस्व व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा



Separate explanation videos are available in English & Hindi

अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं

<p>Prelims 2016 Which of the following are included in the capital budget of the Government of India?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Expenditure on acquisition of assets like roads, buildings, machinery, etc. 2. Loans received from foreign governments 3. Loans and advances granted to the States and Union Territories <p>Select the correct answer (a) 1 only (b) 2 & 3 only (c) 1 & 3 only (d) 1, 2 & 3</p>	<p>निम्नलिखित में से किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय 2. विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण 3. राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम सही उत्तर चुनिए <p>(a) केवल 1 (b) केवल 2,3 (c) केवल 1,3 (d) 1, 2, 3</p>
<p>Prelims 2010</p> <p>In the context of governance, consider the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Encouraging FDI inflows 2. Privatization of higher educational Institutions 3. Down-sizing of bureaucracy 4. Selling/offloading the shares of PSUs <p>Which of the above can be used as measures to control the fiscal deficit in India?</p> <p>(a) 1, 2 and 3 (b) 2, 3 and 4 (c) 1, 2 and 4 (d) 3 and 4 only</p>	<p>निम्नलिखित पर विचार कीजिये:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FDI प्रवाह को प्रोत्साहित करना 2. उच्च शिक्षण संस्थानों का निजीकरण 3. नौकरशाही का आकार कम करना 4. PSU के शेयरों की बिक्री <p>उपर्युक्त में से किसका उपयोग भारत में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उपायों के रूप में किया जा सकता है?</p> <p>(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4 (c) 1, 2 और 4 (d) केवल 3 और 4</p>
<p>Prelims 2016 There has been a persistent deficit budget year after year. Which action/actions of the following can be taken by the Government to reduce the deficit?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reducing revenue expenditure 2. Introducing new welfare schemes 3. Rationalizing subsidies 4. Reducing import duty <p>Select the correct answer (a) 1 only (b) 2 & 3 only (c) 1 & 3 only (d) 1, 2, 3 & 4</p>	<p>साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी कार्रवाई/याँ की जा सकती है?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्व व्यय को घटाना 2. नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना 3. सहायिकी (सब्सिडी) को युक्तिसंगत बनाना 4. आयात शुल्क को कम करना <p>सही उत्तर का चयन कीजिए</p> <p>(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4</p>

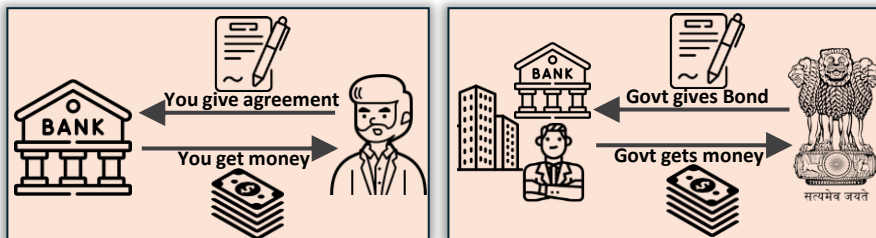
FRBM

<p>Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003</p> <ul style="list-style-type: none"> 2003: Law enacted by Parliament 2017: NK Singh Review Committee 60% General Debt (40% Centre; 20% States) 2018: Act amended Initial target was that by 2008: <ul style="list-style-type: none"> 0% Revenue deficit 3% Fiscal deficit 	<p>राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003</p> <ul style="list-style-type: none"> 2003: संसद द्वारा कानून बनाया गया 2017: NK Singh समीक्षा समिति 60% सामान्य ऋण (40% केंद्र; 20% राज्य) 2018: अधिनियम में संशोधन किया गया प्रारंभिक लक्ष्य यह था कि 2008 तक: <ul style="list-style-type: none"> 0% राजस्व घाटा 3% राजकोषीय घाटा 												
<p>FRBMA mandates 4 policy statements with Budget:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fiscal Policy Strategy Statement 2) Macroeconomic Framework Statement 3) Medium-term Expenditure Framework Statement 4) Medium-term Fiscal Policy Statement <p>➤ It sets 3-year rolling target for the following indicators (as a % of GDP):</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Debt</td> <td>Fiscal deficit</td> </tr> <tr> <td>Tax revenue</td> <td>Revenue deficit</td> </tr> <tr> <td>Non-tax revenue</td> <td>Primary deficit</td> </tr> </table>	Debt	Fiscal deficit	Tax revenue	Revenue deficit	Non-tax revenue	Primary deficit	<p>FRBMA ने बजट के साथ 4 नीतिगत वक्तव्यों को अनिवार्य किया है:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य 2. मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 3. मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा विवरण 4. मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य <p>➤ यह निम्नलिखित संकेतकों के लिए 3-वर्षीय रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करता है (जीडीपी के % के रूप में):</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>ऋण</td> <td>राजकोषीय घाटा</td> </tr> <tr> <td>कर राजस्व</td> <td>राजस्व घाटा</td> </tr> <tr> <td>गैर-कर राजस्व</td> <td>प्राथमिक घाटा</td> </tr> </table>	ऋण	राजकोषीय घाटा	कर राजस्व	राजस्व घाटा	गैर-कर राजस्व	प्राथमिक घाटा
Debt	Fiscal deficit												
Tax revenue	Revenue deficit												
Non-tax revenue	Primary deficit												
ऋण	राजकोषीय घाटा												
कर राजस्व	राजस्व घाटा												
गैर-कर राजस्व	प्राथमिक घाटा												
<p>Escape clause: (relax Fiscal deficit target by 0.5% point)</p> <ul style="list-style-type: none"> act of war; national security; national calamity collapse of agriculture; structural reforms 3% points fall in a quarter's growth, compared to average of previous 4 quarters. 	<p>पलायन खंड: (राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में 0.5% की छूट)</p> <ul style="list-style-type: none"> युद्ध ; राष्ट्रीय सुरक्षा; राष्ट्रीय आपदा कृषि का पतन; संरचनात्मक सुधार पिछली 4 तिमाहियों के औसत की तुलना में एक तिमाही की वृद्धि में 3% अंक की गिरावट 												
<p>Govt failed to meet FRBM target many times. e.g.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Global Financial Crisis of 2008 Link ➤ 01-Feb-2020 Budget, even before Covid Link 	<p>सरकार कई बार FRBM लक्ष्य पूरा करने में विफल रही। जैसे</p> <ul style="list-style-type: none"> 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट 01-फरवरी-2020 बजट, कोविड से पहले ही 												
<p style="text-align: center;">Separate explanation videos are available in English & Hindi</p>													

Govt Securities

NEWS: September 2023 MoneyControl

India will sell 50-year bonds for the first time <https://www.moneycontrol.com/news/business/india-will-sell-50-year-bonds-for-the-first-time-11440121.html>



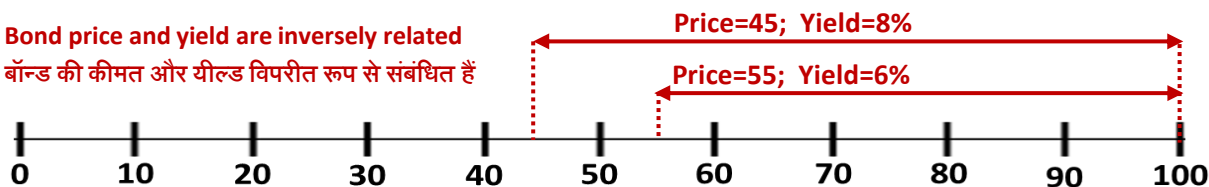
<https://www.rbi.org.in/Scripts/FAQNew.aspx?id=79>

- A bond is a debt instrument.
- Owners of bonds are debt holders, or creditors, of the issuer.
- G-Sec is a tradeable instrument issued by Centre or State.
- G-Sec have practically no risk of default, hence, called risk-free gilt-edged instruments.

- बांड एक ऋण साधन है।
- बांड के मालिक जारीकर्ता के ऋण धारक या लेनदार होते हैं।
- G-Sec केंद्र या राज्य द्वारा जारी एक व्यापार योग्य साधन है।
- G-Sec में व्यावहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिए इसे जोखिम-मुक्त गिल्ट-एज उपकरण कहा जाता है।

Bond price and yield are inversely related

बॉन्ड की कीमत और यील्ड विपरीत रूप से संबंधित हैं



Types of Bond ?

Zero coupon Bond	Give ₹600 now, get ₹1000 later.	अभी ₹ 600 दो, बाद में ₹ 1000 मिलेंगे
Coupon Bond	Give ₹800 now, get ₹1000 later. You will also get ₹20 every 6 months.	अभी ₹ 800 दो, बाद में ₹ 1000 मिलेंगे हर 6 महीने में ₹ 20 भी मिलेंगे
Floating Rate Bond	Give ₹800 now, get ₹1000 later. You will also get something every 6 months.	अभी ₹ 800 दो, बाद में ₹ 1000 मिलेंगे हर 6 महीने में कुछ रुपये जरूर मिलेंगे

FRBs issued by RBI in July 2020 have NSC rate as base and 0.35% over it. ($7.70 + 0.35\% = 8.05\%$).

Here coupon rate will be reset every 1 January and 1 July, i.e. after every 6 months.

जुलाई 2020 में RBI द्वारा जारी FRB में NSC दर के ऊपर 0.35% दिया जाता है। ($7.70 + 0.35\% = 8.05\%$).

इसमें कूपन रेट हर 1 जनवरी और 1 जुलाई, यानी हर 6 महीने के बाद रीसेट किया जाता है।

Government securities (G-sec) ?

- Bonds issued by Government.
- Tenure less than 90 days : **Cash Management Bills**
- Tenure less than 1 year : **T-bills** (issued by only centre)
- Tenure more than 1 year : **dated securities** (issued by both centre and states (State Development Loans))

सरकारी प्रतिभूतियाँ (जी-सेक)?

- सरकार द्वारा जारी बांड
- कार्यकाल 90 दिन से कम : नकद प्रबंधन बिल
- कार्यकाल 1 वर्ष से कम : टी-बिल (केवल केंद्र द्वारा जारी)
- 1 वर्ष से अधिक का कार्यकाल: दिनांकित प्रतिभूतियाँ (केंद्र और राज्य दोनों द्वारा जारी (राज्य विकास ऋण))

Treasury Bills:

- Zero-coupon; issued at discount
- T-bills tenure : 14, 91, 182, 364 days.
- **14 day T-bills are non-marketable.**

ट्रेजरी बिल:

- शून्य-कूपन; छूट पर जारी किए जाते हैं
- अवधि: 14, 91, 182, 364 दिन
- 14 दिन वाले T-बिल व्यापार योग्य नहीं होते हैं

Can NRIs invest in G-sec?

- Yes, but with some **restrictions**.

क्या NRI G-Sec में निवेश कर सकते हैं?

हाँ, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ

<https://www.rbi.org.in/Scripts/FAQNew.aspx?id=79>

- G-Sec are issued through auctions conducted by RBI.
- Auctions are done on E-Kuber, the Core Banking Solution (CBS) platform of RBI.

Participants:

- ✓ Commercial banks
- ✓ Cooperative banks, Regional Rural banks
- ✓ Primary Dealers, Insurance companies
- ✓ Provident funds, Mutual funds, Pension funds
- ✓ Foreign Portfolio Investors (FPIs) and Corporates can also participate.



G-Sec RBI द्वारा नीलामी के माध्यम से जारी किए जाते हैं। नीलामी RBI के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) प्लेटफॉर्म ई-कुबेर पर की जाती है।

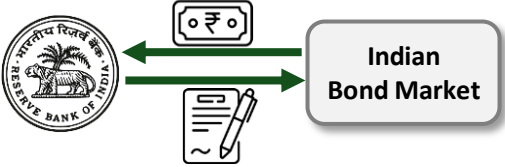
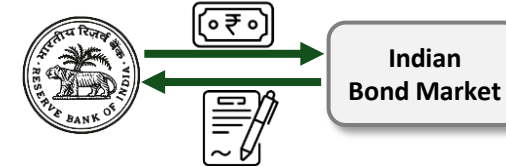
प्रतिभागी:

- ✓ अनुसूचित बैंक
- ✓ सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- ✓ प्राथमिक डीलर, बीमा कंपनियाँ
- ✓ प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड
- ✓ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) और कॉर्पोरेट भी भाग ले सकते हैं।

Separate explanation videos are available in English & Hindi

अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं

Open Market Operations by RBI

<p>Problem? Too much money (liquidity) in market Solution? RBI will suck out money from market How? RBI will sell G-sec in market</p>	<p>Problem? Very less money (liquidity) in market Solution? RBI will pump money into market How? RBI will buy G-sec in market</p>
	
<p>समस्या? बाजार में बहुत अधिक पैसा (तरलता) है समाधान? RBI बाजार से पैसा निकालेगा कैसा? RBI बाजार में G-sec बेचेगा</p>	<p>समस्या? बाजार में बहुत कम पैसा (तरलता) है समाधान? RBI बाजार में पैसा डालेगा कैसा? RBI बाजार में G-sec खरीदेगा</p>
<p>Prelims 2022 With reference to the Indian economy, what are the advantages of "Inflation-Indexed Bonds (IIBs)" ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Government can reduce the coupon rates on its borrowing by way of IIBs. IIBs provide protection to the investors from uncertainty regarding inflation. The interest received as well as capital gains on IIBs are not taxable. <p>Which of the statements given above are correct ? (a) 1 and 2 only (b) 2 and 3 only (c) 1 and 3 only (d) 1, 2 and 3</p>	<p>भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, "मुद्रास्फीति-सहलगन बॉन्ड (inflation indexed bonds IIBs)" के क्या लाभ हैं?</p> <ol style="list-style-type: none"> सरकार IIBs के रूप में अपने ऋणग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। IIBs निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। IIBs पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर-योग्य नहीं होते। <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3</p>
<p>Prelims 2021 Indian Govt Bond Yields are influenced by which of the following?</p> <ol style="list-style-type: none"> Actions of the United States Federal Reserve Actions of the Reserve Bank of India Inflation and short-term interest rates <p>Select the correct answer (a) 1 and 2 only (b) 2 only (c) 3 only (d) 1, 2 and 3</p>	<p>भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होती है?</p> <ol style="list-style-type: none"> यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाइयां मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर <p>सही उत्तर का चयन कीजिए (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3</p>
<p>Prelims 2018 Consider the following statements:</p> <ol style="list-style-type: none"> RBI manages and services Govt. of India Securities but not any State Government Securities. Treasury bills are issued by Govt. of India and there are no treasury bills issued by State Govts. Treasury bills offer are issued at a discount from the par value. <p>Which of the statements given above are correct? (a) 1 and 2 only (b) 3 only (c) 2 and 3 only (d) 1, 2 and 3</p>	<p>निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:</p> <ol style="list-style-type: none"> भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है किन्तु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। भारत सरकार कोष-पत्र (ट्रेजरी बिल) जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष-पत्र जारी नहीं करती। कोष-पत्र ऑफर अपने सममूल्य से बड़े पर जारी किए जाते हैं। <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3</p>
<p>Prelims 2021 With reference to India, consider the following statements:</p> <ol style="list-style-type: none"> Retail investors through demat account can invest in 'Treasury Bills' and 'Government of India Debt Bonds' in primary market. The 'Negotiated Dealing System - Order Matching' is a govt securities trading platform of RBI. The 'Central Depository Services Ltd' is jointly promoted by RBI and Bombay Stock Exchange. <p>Which of the statements given above is/are correct? (a) 1 only (b) 1 and 2 (c) 3 only (d) 2 and 3</p>	<p>भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :</p> <ol style="list-style-type: none"> खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में 'राजकोष बिल' (ट्रेजरी बिल) और 'भारत सरकार के ऋण बांड' में निवेश कर सकते हैं। 'बातचीत से तय लेनदेन प्रणाली - ऑर्डर मिलान' (नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - ऑर्डर मैचिंग) RBI का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। 'सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड' का RBI एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 (b) 1 और 2 (c) केवल 3 (d) 2 और 3</p>
<p>Separate explanation videos are available in English & Hindi</p>	
<p>www.allinclusiveias.com Prelims 2024 Economy</p>	<p>अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं Class-03 Page-018 © All Inclusive IAS</p>